ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 4, July 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

नई शिक्षा नीति एवं ग्रामीण विकास

Dr. Mahesh Kumar Garg

Assistant Professor, Sociology, Government College, Hindaun City, India

सार

शिक्षकों को आवश्यक शैक्षणिक कौशल और ज्ञान से लैस करके, एनईपी यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त हो। यह सहायता प्रणाली समग्र शैक्षिक ढांचे को मजबूत करती है और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए सीखने के परिणामों को बढ़ाती है। नई शिक्षा नीति में कुछ ऐसे बदलाव भी किए गए हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को लाभ होगा। एनईपी में संस्कृत के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओँ पर भी जोर दिया गया है। एनईपी के तहत पांचवी कक्षा तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा में पढाई का माध्यम रखा जाएगा। देश की नई शिक्षा नीति (एनईपी) को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है। देश की शिक्षा नीति को 34 साल बदला गया है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति आई थी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं। सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति में स्कूली पढ़ाई के साथ-साथ वोकेशनल ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा करीकुलर एक्टिविटीज़ को भी अहमियत दी जाएगी जिससे छात्रों के पूर्ण विकास में मदद मिलेगीऔर रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। नई शिक्षा नीति में कुछ ऐसे बदलाव भी किए गए हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को लाभ होगा। एनईपी में संस्कृत के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओँ पर भी जोर दिया गया है। एनईपी के तहत पांचवी कक्षा तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा में पढाई का माध्यम रखा जाएगा। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा संस्थानों में गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की संख्या बढ़ाने की भी बात की गई है। आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति का ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या असर होगा.

परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से इन बड़े अंतरालों को बहुत गंभीरता से लिया है। एन.ई.पी. ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से इसे दूर करने का लगातार प्रयास किया है। एन.ई.पी. 2020 का दृष्टिकोण समग्र और यथार्थवादी भी है क्योंकि भारत गांवों का देश है। हमारी 60 प्रतिशत आबादी कृषि गतिविधियों और उत्पादन पर निर्भर है। हमारे छात्र लोग विषम परिवेशों से आते हैं। वे कई धर्मों, बहुभाषी पृष्ठभूमि और बहु आर्थिक स्तरों से हैं। पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों से छात्र समुदाय को संबोधित करने की अपेक्षा की जाती है।

आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में समस्या अधिक जटिल है। कई छात्रों को भाषा के कारण सीखने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उनमें से कई छात्र ऐसे भी हैं जो विविध छात्र समुदाय तक पहुंचने वाली पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं। शिक्षक को बहुआयामी व्यक्तित्व वाला और आजीवन सीखने वाला भी होना चाहिए। आधुनिक दुनिया की अप्रत्याशित तकनीक ने दुनिया को और प्रतिस्पद्र्धात्मक बना दिया है। विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के डी.एन.ए. में कोई न कोई कौशल अवश्य होता है।

वे परिवार के घरेलू कामकाज में भी भाग लेंगे और कई बार अपने पारिवारिक कौशल, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, बढ़ईगिरी, लोहार, सुनार आदि कार्य में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। लेकिन वर्तमान की पाठ्य पुस्तकों और उनके पारिवारिक कौशल के बीच कोई समन्वय नहीं है। एन.ई.पी. 2020 हमारी कृषि, हमारे जल निकाय, पोखर, जल संसाधन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी पालन आदि को हमारी पाठ्यपुस्तकों में शामिल करने पर जोर देती है। यह एक ऐसी समाज की परिकल्पना करती है जिसमें समाज और कक्षा का वातावरण अनुकूल हो। कौशल शिक्षा के प्रवर्तक के रूप में एन.ई.पी. 2020 पाठ्यक्रम के व्यावसायीकरण के माध्यम से सीधे शिक्षा जगत एवं उद्योग जगत में संबंध स्थापित कर रही है और युवाओं को बढ़ईगिरी, लोहारी, यांत्रिकी, मुरम्मत कार्यशालाओं आदि में प्रशिक्षण जैसे आय-सृजन कौशल और उद्यमिता सिखाकर उन्हें सशक्त बना रही है। छात्रों के अंतर्निहित कौशल के संवर्धन के लिए यह अति आवश्यक है। इसके अलावा, आने वाले समय में विश्लेषणात्मक कौशल जैसे प्रतिभा प्रबंधन, ग्राहक सेवा उद्योग का विकास, कृषि, डिजिटल वाणिज्य, डाटा विज्ञान और व्यापार में बड़े पैमाने पर नौकरी में वृद्धि की उम्मीद है। भविष्य की नौकरियों के लिए भविष्य के कौशल को बढ़ावा देने के लिए एन.ई.पी. 2020 ध्यान केंद्रित करती है।

एन.ई.पी. 2020 का लक्ष्य दुनिया के सामने भारत की सौम्य शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए अनुसंधान और विकास को मजबूत करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय लोक संस्कृति और मौखिकता पर आधारित अनुसंधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारतीय ज्ञान प्रणाली को एन.टी.ए.-नेट विषय के रूप में मान्यता मिलना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। उच्च शिक्षा संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में योग अध्ययन की स्थापना के साथ, आयुर्वेद शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्वास्थ्य

सेवा प्रणाली में आयुष डॉक्टरों को शामिल करना, भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करने के लिए आई.सी.सी.आर. का बजट बढ़ाना एन.ई.पी. के तहत उठाया गया एक बड़ा कदम है।

इसके अलावा, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली को वैश्विक मान्यता दिलाने का दृष्टिकोण लगातार आगे बढ़ रहा है। हैल्थकेयर में आर. एंड डी. का महत्व बढ़ाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक निर्णायक उपलब्धि है, जिसके तहत वैक्सीन का विकास, सिकल सैल एनीमिया और थैलेसीमिया के लिए लगभग 89,155 करोड़ के बजट का आबंटन, आदि हमें 'फिट इंडिया, हिट इंडिया' के उद्देश्य को हासिल करने के लिए मदद कर सकता है। एन.ई.पी. 2020 अनुसंधान, विपणन और स्थानीय उत्पादन पर मुखर है। यदि हम आयात कम करें और निर्यात बढ़ाएं तो स्वाभाविक रूप से किसान की आय दोगुनी और लाभदायक होगी। घरेलू उद्योग, लघु उद्योग, खादी और ग्राम उद्योग, मिट्टी के बर्तन उद्योग का वैश्विक परिदृश्य पर एक बड़ा बाजार है। जब शिक्षा और समाज के बीच कोई अंतर नहीं होगा, तो उद्योग स्वचालित रूप से शिक्षा एवं अनुसंधान के मैदान में प्रवेश करने में बहुत रुचि लेंगे। नौकरी चाहने वाले नौकरी देने वाले बन जाएंगे। शिक्षा जगत की गतिशीलता अधिक जीवंत और समावेशी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक संवेदनशील नागरिक समाज बनाएगी और यह समाज, प्रौद्योगिकियों, कृषि और सामाजिक विज्ञान में नवाचारों को बढ़ावा देगा।

विचार-विमर्श

हाल के दिनों में, समाज विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं को देख रहा है जो लोगों के जीवन, संस्कृति और आजीविका को प्रभावित करती हैं। एक अभ्यास और अनुशासन के रूप में, 'सामाजिक कार्य' लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में होने वाली इन गतिशीलता को विभिन्न तरीकों से शामिल करता रहा है। सामान्य तौर पर एक अभ्यास-उन्मुख अनुशासन के रूप में, (पेशेवर) सामाजिक कार्य को भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजनों के बावजूद व्यक्तियों, समूहों और समुदायों से निपटने में अपना कार्य वितरित किया गया है। यह वह आधार है जिसमें हम सामाजिक कार्य के विकास और विस्तार की कल्पना और अनुमान लगाते हैं जो इसके लक्षित समूहों के बीच जिम्मेदार हस्तक्षेप करता है और इस प्रकार उनके जीवन और आजीविका को बढ़ाता है। हाल के दिनों में, कोविड-19 की महामारी, जिसके कारण लाखों लोग शहरों से वापस अपने गांवों की ओर पलायन करने लगे, भारत में गरीबी और हाशिए पर जाने की सीमा तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संबंध का प्रतीक था। गौरतलब है कि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जब हमें इन पैटर्न की आकस्मिकताओं और समकालीन में उनके निहितार्थों पर गौर करने की जरूरत है।

तुलजापुर में स्कूल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, स्नातक से डॉक्टरेट स्तर तक सामाजिक कार्य कार्यक्रम पेश कर रहा है। मराठवाड़ा क्षेत्र के आसपास इसका स्थान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि जैसे क्षेत्र के विकास संबंधी प्रश्नों पर संकाय और छात्रों के लिए पर्याप्त जुड़ाव की अनुमति देता है। पिछले कुछ दशकों में क्षेत्र के हस्तक्षेप, अनुसंधान और अभ्यास के रूप में पाठ्यक्रम के साथ घनिष्ठ संबंध के माध्यम से संकाय सदस्यों द्वारा की गई पहल ने TISS को ग्रामीण महाराष्ट्र में एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित किया है। ग्रामीण विकास शिक्षा, अनुसंधान के साथ-साथ सूक्ष्म से वकालत स्तर तक अभ्यास में लगे एक अकादमिक संस्थान के रूप में अपनी साख को मजबूत करने की दिशा में, हम वर्तमान में समकालीन ग्रामीण भारत में सामाजिक कार्यों पर संवाद को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया में हैं।

यह दिलचस्प और सामाजिक कार्य के अनुशासन के विकास के लिए अनुकूल होगा यदि हम क्षेत्र के साथ-साथ कक्षा में भी अपनी चिंताओं पर विचार-विमर्श और बहस कर सकें - 'ग्रामीण' संदर्भ में सामाजिक कार्य को सबसे आगे लाने के लिए। यह शुरुआत में यह स्वीकार करके सूचित किया जा सकता है कि भारत में शहरीकरण की प्रकृति ग्रामीण से निकटता से जुड़ी हुई है। कुछ प्रश्न जिनसे हम शुरुआत करते हैं वे हैं: ग्रामीण भारत में आबादी की वर्तमान चिंताएँ क्या हैं? सामाजिक कार्य अभ्यास और शिक्षा किस हद तक इन चिंताओं का समाधान करती है? अंतःविषय दृष्टिकोण के साथ, हम अपने विश्लेषण और अभ्यास को कैसे मजबूत कर सकते हैं? ग्रामीण वास्तविकताएँ शहरी वास्तविकताओं से कितनी भिन्न हैं? क्या ग्रामीण समुदायों के लिए विशिष्ट प्रथाओं के लिए तालमेल बनाना संभव है? अभ्यास को प्रासंगिक बनाने के लिए देश भर में विविधता के क्या निहितार्थ हैं? हमें अनुशासन और पेशे को अधिक प्रासंगिक बनाने और निश्चित और समग्र ढांचे से आगे बढ़ने के लिए इन सवालों से जुड़ना चाहिए। सामाजिक न्याय की दिशा में काम करते समय, क्या इस बात की फिर से जांच करने की आवश्यकता है कि क्या अभ्यास के वर्तमान मॉडल उन लोगों के सशक्तिकरण और मुक्ति के लिए प्रासंगिक हैं जिनके साथ हम काम करते हैं? क्या सामाजिक कार्य के स्वदेशीकरण की भाषा ग्रामीण समाजों में प्रचलित उत्पीड़न और पराधीनता के अनुभवों को संबोधित करने में सक्षम है? या क्या हमें हाशिये पर मौजूद आबादी पर ध्यान देने की ज़रूरत है; विशेषकर दलित, आदिवासी, अन्य व्यावसायिक समूह? क्या इस बात की फिर से जांच करने की आवश्यकता है कि क्या अभ्यास के वर्तमान मॉडल उन लोगों के सशक्तिकरण और मुक्ति के लिए प्रासंगिक हैं जिनके साथ हम काम करते हैं? क्या सामाजिक कार्य के स्वदेशीकरण की भाषा ग्रामीण समाजों में प्रचलित उत्पीड़न और पराधीनता के अनुभवों को संबोधित करने में सक्षम है? या क्या हमें हाशिये पर मौजूद आबादी पर ध्यान देने की ज़रूरत है; विशेषकर दलित, आदिवासी, अन्य व्यावसायिक समूह? क्या इस बात की फिर से जांच करने की आवश्यकता है कि क्या अभ्यास के वर्तमान मॉडल उन लोगों के सशक्तिकरण और मुक्ति के लिए प्रासंगिक हैं जिनके साथ हम काम करते हैं? क्या सामाजिक कार्य के स्वदेशीकरण की भाषा

ग्रामीण समाजों में प्रचलित उत्पीड़न और पराधीनता के अनुभवों को संबोधित करने में सक्षम है? या क्या हमें हाशिये पर मौजूद आबादी पर ध्यान देने की ज़रूरत है; विशेषकर दलित, आदिवासी, अन्य व्यावसायिक समूह?

उपरोक्त अस्पष्टताओं के भीतर और आसपास खुद को स्थापित करते हुए, हम ग्रामीण समाजों में सामाजिक कार्य के सिद्धांत और व्यवहार को मजबूत करने के लिए छात्रों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, कार्यकर्ताओं, विद्वानों और शिक्षकों के साथ संवाद और विचार-विमर्श के लिए एक मंच बनाने के मिशन पर हैं। इसलिए हम 25 और 26 अगस्त 2021 को होने वाले ग्रामीण समाजों में सामाजिक कार्य: पद्धति और अभ्यास पर विचार विषय पर अपने राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन की घोषणा करते हैं।

कॉल फ़ॉर पेपर्स

हम क्षेत्र, सिद्धांत, या/और साहित्य पर आधारित अकादमिक अन्वेषणों के रूप में पेपर आमंत्रित करते हैं जो ग्रामीण सामाजिक कार्यों के लिए नए विचारों और दिशाओं का वादा करते हैं। इस आयोजन के लिए निम्नलिखित उप-विषयों के तहत पेपर आमंत्रित किए जाते हैं, जिनमें अधिकतम 500 शब्दों के सार के साथ rswconfo.tisstuljapur@gmail.com पर भेजा जाना है। सार को अपना केंद्रीय शोध प्रश्न व्यक्त करना चाहिए और शीर्षक, उप-विषय और लेखक के बारे में विवरण का उल्लेख करना चाहिए। चयनित सार के लेखकों को 10 अगस्त 2021 से पहले पूरा पेपर जमा करना होगा।

उप-विषय हैं :

- ग्रामीण सामाजिक कार्य की परिभाषा, सिद्धांत और अभ्यास
- ग्रामीण विकास और इसकी लक्षित आबादी
- कृषि समाजों में सामाजिक कार्य हस्तक्षेप
- ग्रामीण समाज की राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक कार्य पद्धति
- सामाजिक कार्य और ग्रामीण सरोकारों का स्वदेशीकरण
- स्थानीय-स्वशासन और ग्रामीण समुदायों के साथ सामाजिक कार्य
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका
- नई शिक्षा नीति एवं सामाजिक कार्य का अनुशासन।
- सामाजिक कार्य अभ्यास के लिए विचारधाराएँ: मार्क्स, गांधी, अम्बेडकर, फुले, और अन्य
- ग्रामीण समाज में दलित, आदिवासी, दमन-विरोधी और कट्टरपंथी सामाजिक कार्य: शिक्षण और अभ्यास के लिए पाठ।

परिणाम

तकनीकी उन्नयन और समावेशी विकास ग्रामीण भारत में विकास के केंद्र बिंदु रहे हैं। उच्च और बेहतर उत्पादकता, सामाजिक-आर्थिक समानता, आधुनिक प्रौद्योगिकी का सामंजस्य और सतत विकास को किसी देश की प्रगति के स्तंभ माना जा सकता है। भारत सरकार ने शिक्षा से लेकर वित्तीय साक्षरता और कृषि तकनीक से लेकर कौशल विकास तक योजनाएं शुरू की हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 900 मिलियन लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं। यह देखना सराहनीय है कि केंद्र और राज्य सरकारें ग्रामीण भारत की बेहतरी के दृष्टिकोण के साथ एकजुट हैं। डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी ने श्रम बाजार को मजबूत किया है और शिक्षित होने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए एक मंच प्रदान किया है। उन्नत नवाचार ने ग्रामीण क्षेत्रों को अपनी विकास संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद की है. ग्रामीण भारत हमारे देश की कुल जनसंख्या का 65% निवास करता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी 2017-18 में 35.3% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 36.1% और 2019 में 38% हो गई है। 20. केंद्र ने कृषि में विशिष्ट योजनाओं और तकनीकी प्रगति को लागू करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का वादा किया है।

अप्रैल 2016 में, भारत सरकार ने किसानों के लिए एक ऑनलाइन मंच ई-एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) लॉन्च किया, जो एक राष्ट्र, एक बाजार की थीम के साथ पूरे भारत के कृषि बाजारों को एकीकृत करता है। यह प्लेटफ़ॉर्म किसानों और व्यापारियों को सभी कृषि उपज बाज़ार समिति (एपीएमसी) से संबंधित जानकारी, कमोडिटी आगमन, और व्यापार ऑफ़र खरीदने और बेचने में सहायता करता है, इस प्रकार किसानों को बाजारों में सर्वोत्तम कीमतों के लिए बोली लगाने में मदद मिलती है। इसका उद्देश्य कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ावा देना और खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता को दूर करना था। पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़कर 1.66 करोड़ हो गई है, जबकि 1.28 लाख व्यापारी इस प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करते हैं। इस मंच पर 1000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) भी पंजीकृत हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई, जो शिक्षा तक मल्टी-मोड पहुंच प्रदान करने के लिए सभी-डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन-एयर शिक्षा को जोड़ती है। इस पहल में निम्नलिखित शामिल हैं:

- दीक्षा (नॉलेज शेयरिंग और शेयरिंग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर) एक-राष्ट्र, एक-डिजिटल-प्लेटफ़ॉर्म पहल है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में, देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा शिक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री प्रदान करता है।
- स्वयं (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों: पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इस पहल का लक्ष्य सभी के लिए सर्वोत्तम शिक्षण-शिक्षण उपकरण उपलब्ध कराना है, विशेषकर सबसे वंचित लोगों के लिए। जो छात्र डिजिटल क्रांति से वंचित रह गए हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने में असमर्थ हैं, उनके लिए SWAYAM का लक्ष्य डिजिटल विभाजन को पाटना है। यह एक ऐसा मंच है जो किसी को भी, कहीं भी, किसी भी समय कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर तक कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों तक पहुंचने की अनुमति देता है। सभी पाठ्यक्रम इंटरैक्टिव हैं, जिन्हें देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों द्वारा डिज़ाइन किया गया है, और पूरी तरह से निःशुल्क हैं।

भारत जैसे देश में, जहां अधिकांश आबादी अभी भी ग्रामीण इलाकों में रहती है, ग्रामीण विकास भारत की विकास कहानी का पर्याय है। जबकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हमेशा प्राथमिकता रही है, डिजिटलीकरण की शुरुआत ने ग्रामीण विकास की गति को तेज कर दिया है। वर्तमान में भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास हो रहा है, उसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय बात इस विकास की समावेशिता और स्थिरता है। जन धन योजना जैसी योजनाएं ग्रामीण भारत में काफी सफल रही हैं और कृषि गतिविधियों को आधुनिक, हरित तरीकों की ओर धकेला जा रहा है, इस विकास की समावेशिता और स्थिरता के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है।

निष्कर्ष

श्री तोमर ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बताते हुए नई शिक्षा नीति के माध्यम से कृषि शिक्षा को और भी अधिक रोजगारोन्मुखी तथा उन्नत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिए गए नीतिगत-निर्णयों, योजनाओं, कानूनी रिफ़ार्म्स (जिसके अंतर्गत किसान अब अपनी उपज को उचित कीमत और मनचाहे स्थान पर बेच सकते हैं) और कांट्रेक्ट फ़ार्मिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश आज किसानों के परिश्रम और वैज्ञानिकों के अनुसंधान के कारण उत्पादन केंद्रित होकर खाद्यान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि दलहन, तिलहन, दुग्ध आदि के उत्पादन में हम दुनिया के पहली और दूसरी नंबर पर कायम हैं।

केंद्रीय मंत्री ने प्राकृतिक प्रतिकूलता से हो रही समस्याओं से निजात के लिए क्षेत्रीय समितियों की ऐसी बैठकों को अनिवार्य बताते हुए कृषि क्षेत्र को प्रौद्योगिकी से जोड़ने तथा उसे मुनाफे व आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए ज़ोर दिया। श्री तोमर ने किसानों के हित में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि 10000 नए किसान उत्पादक संगठनों के गठन का निर्णय सराहनीय है जो किसानों को कृषि उत्पादन के दौरान प्रौद्योगिकी, बेहतर बीज, उर्वरक, कीटनाशक, समुचित वित्त और उत्पादों के विपणन जैसी बड़ी चुनौतियों से राहत दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा।

श्री परषोत्तम रूपाला, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करने के लिए क्षेत्रीय समिति की ऐसी बैठकों का होते रहना इसलिए भी जरूरी है ताकि विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के अनुरूप उचित समाधान की चेष्टा की जा सके। ऐसे प्रयासों व ऐसी बैठकों के लिए उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सराहना की। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के अनुसंधान, किसानों के अथक परिश्रम, समितियों की बैठकों व समीक्षाओं से ही हम 2022 तक किसानों की दोगुनी आय का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश में बीज प्रतिस्थापन (Seed Replacement) से संबंधित उपलब्धियों की जानकारी दी तथा इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कृषि-शिक्षा एवं किसानों के बीच प्रौद्योगिकियों के प्रसार संबंधी गतिविधियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने आग्रह किया कि बदलते परिस्थिति के मद्देनजर जलवायु अनुकूल परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाए।

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. "नई शिक्षा नीति: पढ़ाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सब में होंगे ये बड़े बदलाव". आज तक. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
2. ↑ "नई शिक्षा नीति पर BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले- नई शिक्षा नीति नए भारत की जरूरतों को ध्यान में रखती है". पंजाब केसरी. 29 जुलाई 2020. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
3. ↑ नई शिक्षा नीति, 2020
4. ↑ "नई शिक्षा नीति-2020: प्रमुख पॉइंट्स एक नजर में". 30 जुलाई 2020. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
5. ↑ "आइए जानें आखिर देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ी". दैनिक जागरण. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
6. ↑ Rohatgi, Anubha, संपा° (2020-08-07). "Highlights | NEP will play role in reducing gap between research and education in India: PM Modi". Hindustan Times. अभिगमन तिथि 2020-08-08.
7. ↑ "New Education Policy 2020 : 5वीं तक पढ़ाई अब मातृभाषा में, स्नातक तक प्रवेश की एक परीक्षा". अमर उजाला. अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020.
8. ↑ "नई शिक्षा नीति". नवभारत टाइम्स. अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020.
9. ↑ "नई शिक्षा नीति: पढ़ाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सब में होंगे ये बड़े बदलाव". आज तक. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
10. ↑ "नई शिक्षा नीति 2020 : स्कूल एजुकेशन, बोर्ड एग्जाम, ग्रेजुएशन डिग्री में हुए बड़े बदलाव, जानें 20 खास बातें". हिन्दुस्तान लाइव. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.[मृत कड़ियाँ]
11. ↑ सिंह, प्रोफेसर दिनेश (29 जुलाई 2020). "स्कूली और उच्च शिक्षा की बेड़ियां खोलेगी नई शिक्षा नीति". द क्विंट. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
12. ↑ "New Education Policy: अब केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक, फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़ सकेंगे छात्र". आज तक. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.
13. ↑ "नई शिक्षा नीति से कितनी बदलेगी शिक्षा व्यवस्था? जानिए-क्या कहते हैं जानकार". आज तक. अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020.
14. ↑ "नई शिक्षा नीति का समर्थन कर शशि थरूर बोले- कई लक्ष्य सच्चाई से परे, बजट पर चिंता". आज तक. अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020.
15. ↑ सिंह, सरोज (30 जुलाई 2020). "नई शिक्षा नीति 2020: सिर्फ़ आरएसएस का एजेंडा या आम लोगों की बात भी". बीबीसी हिन्दी. अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020.
16. ↑ NEP 2020: Student, Teacher Bodies Call The New Education Policy 'Anti-democratic'

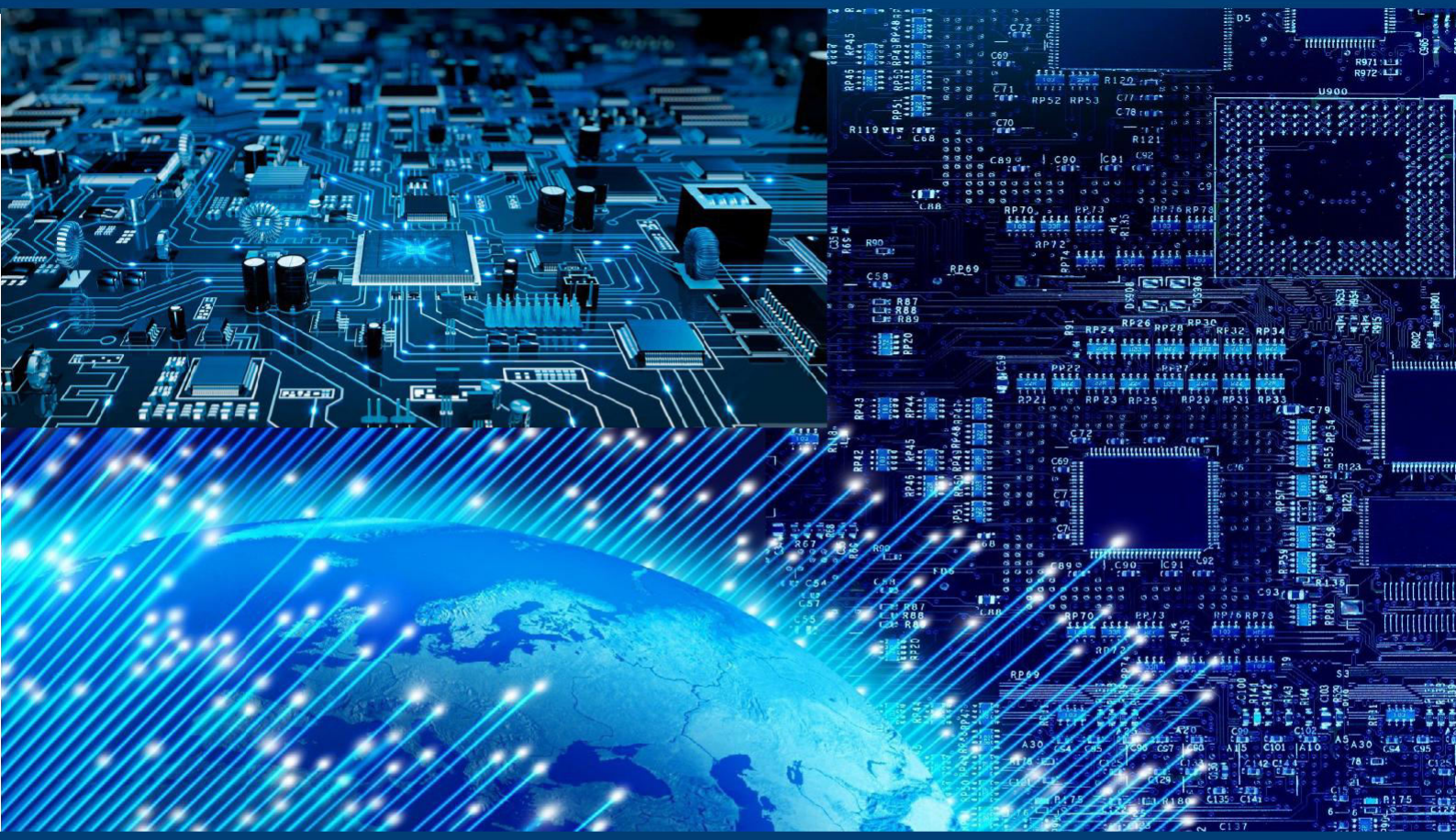

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |